इस संबंध में किन्हीं शर्तों का अनुपालन भी किया जा रहा है;

(घ) क्या विदेशों से आयात किया जाने वाला कोयला भारत में उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कोयला आयात करने के क्या कारण हैं और घरेलू कोयला बाजार पर कोयले के आयात का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) उदारीकृत निर्यात-आयात नीति, 1992-97 के अन्तर्गत सभी लोगों को कोयले का बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति है । मुक्त रूप आयात किए जाने की अनुमति को देखते हुए मूल्य, मात्रा तथा क्वालिटी और आयात-स्रोत की दृष्टि से कोयले के संभावित आयात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

(घ) तथा (ङ) धुले हुए कोकिंग कोयले का स्वदेशी उत्पादन देश के इस्पात संयंत्रों की स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । इसलिए, मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को पाटने के लिए मिश्रण प्रयोजन हेतु कम राख वाले कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है ।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की प्रभाविता

4328. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 मार्च, 1994 के दैनिक "पायनियर" में "हाऊ एफैक्टिव आर०ई०पी०जेड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ वर्षों से निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जा रहे निर्यात के मूल्य की प्रतिशतता में देश के कुल निर्यात मूल्य के संदर्भ में निरंतर कमी आ रही है;

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में देश से होने वाले कुल निर्यात मूल्य का कितना प्रतिशत इन शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया गया है;

(घ) क्या उक्त वर्षों के दौरान इन इकाइयों द्वारा आयात भी किया गया है; यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में इन इकाइयों द्वारा वर्ष-वार कितने-कितने मूल्य का आयात किया गया; और

(ङ) क्या सरकार ने इन औद्योगिक इकाइयों के कार्यकरण की समीक्षा की है; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) पूर्ववर्ती सोवियत संघ में बाजार अव्यवस्था के कारण वर्ष 1992-93 में आई एक छोटी-सी गिरावट को छोड़कर निर्यात प्रोसेसिंग जोनों से किये गये निर्यात में राष्ट्रीय निर्यात की तरह तीव्र वृद्धि रही है जैसाकि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष	देश के निर्यात का कुल मूल्य (करोड़ रु०)	निर्यात प्रोसेसिंग जोनों के कुल निर्यात का मूल्य	प्रतिशतता
1991-92	44042	1177	2.67
1992-93	53686	1376	2.56
1993-94 (फरवरी, 1994 तक)	62181	1641	2.64

(घ) जी, हां । निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में स्थित एककों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आयात का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	आयात मूल्य (करोड़ रु०)
1991-92	751.55
1992-93	936.51
1993-94 (अनन्तिम)	1349.71

(ङ) व्यापारियों और उद्योगियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर इस योजना के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए उपाय किए गए हैं ।

Non-product and product specific subsidies on agriculture

4329. SHRI BHUPENDER SINGH MANN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what are the figures about non-product specific subsidies and product specific subsidies on agriculture during the last three years; and

(b) what steps Government are taking to correct this injustice to farmers ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) The Uruguay Round Agreement on Agriculture requires calculation of product specific and non-product specific Aggregate Measurements of Support (AMS) for the base period (1986—88) only and not for subsequent years. The requisite information in respect of the base period is contained in the schedule of commitments to the GATT, a copy of which is available in the Parliament Library. This Ministry has not made any calculation of AMS beyond the base period.

Marketing of Indian Books In Foreign Countries

4330. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has become a dumping ground for foreign scientific, technical and medical books;

(b) whether it is also a fact that Indian Books are cheaper yet foreign booksellers are reluctant to stock them ;

(c) whether Government have identi fied the reasons of the same and if so, the details thereof ; and

(d) what incentive Government pro pose to give to boost their sales in foreign countries ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) Foreign scientific, technical and medical books are allowed to be imported into India.

(b) and (c) As per available information, foreign booksellers for historical reasons do not favour Indian publications and continue to promote western publications. Therefore, despite Indian books being cheaper, booksellers in developed countries are reluctant to stock and sell Indian books.

(d) Under the Export-Import Policy, 1992—97, export of books and publications are allowed freely, Marketing Development Assistance (MDA) is granted to the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council, Calcutta, annually which also helps to boost the export of books and publications. No special dispensation is granted to any industry in this regard.

Agricultural and Drug Price increase due to GATT ACCORD

4331. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to an OECD report agricultural prices are likely to rise by four to seven per cent and drug prices by 14 to 16 per cent due to the implementation of the GATT accord ; and

(b) if so, what steps Government intend to take to contain this projected rise in prices ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) The OECD study entitled 'Assessing the effects of the Uruguay Round' does not deal with the likely increase in prices of agricultural products and drugs due to the implementation of the Uruguay Round Agreement.

(b) The Uruguay Round Agreement does not impose any restrictions on the use of price control measures which may be resorted to incase of an increase in prices.

Resentment of ESCAP Members on Social issue condition at I.T.A.

4332. SHRI V. NARAYANASAMY :
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the resent 50th Ministerial session of ESCAP, a number of member countries including South Korea, Malaysia, Bangladesh and Hongkong displayed solidarity with India in assailing the attempts being made by some developed countries to put out social issues of environment and labour standards at the International Trade Agenda ;